

अवैध रेत खनन

प्रलिस के लयः

रेत खनन, खान और खनजि (वकिस और वनियमन) अधनियम, 1957, खान और खनजि (वकिस और वनियमन) संशोधन अधनियम, 2023, रेत खनन 2020 के लयि परवरतन और नगिरानी दशानरिदेश, वनिरिमति रेत (एम-रेत)

मेन्स के लयः

भारत में समुद्री रेत नषिकरण, रेत खनन के पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव ।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बहिर पुलसि ने [अवैध रेत खनन](#) के खलिफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रेत तस्करों को गरिफ्तार कयि था ।

- [सोन नदी](#) के पास यह ऑपरेशन अवैध रेत खनन गतविधियों में शामिल शक्तशाली आपराधिक सडिकेट के खलिफ चल रही लड़ाई में एक महत्त्वपूर्ण कदम का प्रतीक है ।

रेत खनन क्या है?

- **परचियः**
 - रेत खनन को बाद के प्रसंस्करण के लयि मूल्यवान **खनजिों, धातुओं, पत्थर, रेत और बजरी** को नकिलने के लयि **प्राकृतिक पर्यावरण** (स्थलीय, नदी, तटीय या समुद्री) से प्राथमिक प्राकृतिक रेत और रेत संसाधनों (खनजि रेत और समुचय) को हटाने के रूप में परभाषति कयि गया है । वभिन्न कारकों से परेरति यह गतविधि **पारस्थितिक तंत्र और समुदायों के लयि गंभीर खतरा** पैदा करती है ।
- **भारत में रेत का स्रोतः**
 - सतत रेत खनन **प्रबंधन दशा-नरिदेश (SSMMG)** 2016 सुझाव देते हैं कभारत में रेत के स्रोत हैं
 - नदी (नदी तटवर्ती और बाढ़ का मैदान),
 - झीलें और जलाशय,
 - कृषिक्षेत्र,
 - तटीय/समुद्री रेत,
 - पैलियो-चैनल,
 - नरिमति रेत (एम-सैंड) ।
- **अवैध रेत खनन में योगदान देने वाले कारकः**
 - **वनियमन और परवरतन का अभावः**
 - अपर्याप्त नयामक ढाँचे और कमजोर परवरतन तंत्र अवैध रेत खनन के प्रसार में योगदान करते हैं ।
 - **नरिमाण सामग्री की उच्च मांगः**
 - **नरिमाण उद्योग में रेत ईधन की भारी मांग के कारण अवैध उत्खनन** हो रहा है, जसिसे नरिमाण परयोजनाओं में रेत की बढ़ती आवश्यकता के कारण नदी तलों और तटीय क्षेत्नों पर दबाव बढ़ रहा है ।
 - तेज़ी से **जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण** के कारण नरिमाण की आवश्यकता बढ़ गई है, जसिसे रेत की मांग बढ़ गई है ।
- **भ्रष्टाचार और माफिया प्रभावः**
 - भ्रष्ट आचरण और संगठति **रेत माफियाओं** का प्रभाव अवैध खनन को जारी रखने में योगदान देता है ।
 - अधिकारियों और अवैध ऑपरेटरों के बीच मलीभगत रेत खनन उद्योग को नरितंत्रति तथा वनियमति करने के प्रयासों को कमजोर करती है ।
- **स्थायी वकिल्पों का अभावः**
 - **वनिरिमति रेत (M-sand)** जैसे टकिऊ वकिल्पों को सीमति रूप से अपनाने से नदी तल की रेत पर अत्यधिक नरिभरता में योगदान होता है ।

- पर्यावरण-अनुकूल वकिलों का अपर्याप्त प्रचार प्राकृतिक रेत की मांग को बनाए रखता है, जिससे पर्यावरणीय परिणाम बगिड़ते हैं।
- **कमजोर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) कार्यान्वयन:**
 - रेत खनन गतिविधियों के लिये EIA का अप्रभावी कार्यान्वयन अनधिकृत नषिकरण की अनुमति देता है।
 - अपर्याप्त जन जागरूकता और नगिरानी तंत्र अवैध खनन गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिये जाने में योगदान करते हैं।
- **रेत खनन के परिणाम:**
 - **कटाव और आवास वधितन:**
 - **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)** का कहना है कि अनियमित रेत खनन से नदी तल बदल जाता है, जिससे **कटाव** बढ़ जाता है, चैनल आकारकी में बदलाव होता है और जलीय आवासों में व्यवधान होता है।
 - रेत खनन से धारा चैनलों में स्थिरता का नुकसान होता है, जिससे खनन पूर्व आवास स्थितियों के लिये अनुकूलित देशी प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा होता है
 - **बाढ़ और बढ़ा हुआ अवसादन:**
 - नदी तल से रेत की कमी नदियों और तटीय क्षेत्रों में **बाढ़** तथा **अवसादन में वृद्धि** में योगदान करती है।
 - परिवर्तित प्रवाह पैटर्न और तलछट भार जलीय पारस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, **जिससे वनस्पति तथा जीव दोनों प्रभावित होते हैं।**
 - **भूजल का ह्रास:**
 - रेत खनन के कारण बने गहरे गड्ढे **भूजल सत्र** में गिरावट का कारण बन सकते हैं।
 - यह **स्थानीय पेयजल कुओं** को प्रभावित करता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में **जल की कमी** हो जाती है।
 - **जैव-विविधता हानि:**
 - रेत खनन जैसी गतिविधियों से उत्पन्न आवास व्यवधान तथा क्षरण से **जैवविविधता को गंभीर** क्षति होती है, जिससे जलीय एवं तटवर्ती दोनों प्रजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके विनाशकारी प्रभाव **मैक्रोव** तक व्याप्त हैं।

भारत में रेत खनन को रोकने के लिये क्या पहल की गई है?

- **खान और खनजि विकास तथा वनियमन अधिनियम, 1957 (MMDR अधिनियम):**
 - **खान और खनजि (विकास और वनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR अधिनियम)** के तहत रेत को "लघु खनजि" के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा लघु खनजि पर प्रशासनिक नियंत्रण **राज्य सरकारों** के अधीन है।
 - MMDR अधिनियम की धारा 3(e) का उद्देश्य सरकार द्वारा अवैध प्रथाओं पर अंकुश लगाने के साथ अवैध खनन को रोकना है।
 - **MMDR अधिनियम, 1957 में संशोधन** के लिये **खान और खनजि (विकास और वनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023** हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया था।
- **2006 पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA):**
 - भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि **सभी रेत खनन संग्रहण गतिविधियों (5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रों में भी) के लिये अनुमोदन आवश्यक है।**
 - इस नरिणय का उद्देश्य पारस्थितिक तंत्र पर रेत खनन के गंभीर प्रभाव का समाधान करना है, जो पौधों, पशुओं तथा नदियों को प्रभावित करता है।
- **सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश (SSMG) 2016:**
 - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा जारी, इन दिशानिर्देशों के मुख्य उद्देश्यों में पर्यावरण की दृष्टि से सतत तथा सामाजिक रूप से ज़िम्मेदारीपूर्ण खनन, पारस्थितिक तंत्र की सुरक्षा व बहाली द्वारा **नदी संतुलन** एवं उसके प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, प्रदूषण से सुरक्षा तथा नदी जल की कमी व भूजल भंडार की कमी को रोकना शामिल है।
- **रेत खनन हेतु प्रवर्तन और नगिरानी दिशानिर्देश 2020:**
 - ये दिशानिर्देश **पूरे भारत में रेत खनन की नगिरानी के लिये एक समान प्रोटोकॉल** प्रदान करते हैं।
 - दिशानिर्देशों में रेत खनजि स्रोतों की पहचान, उनके प्रेषण और उनके अंतिम उपयोग को शामिल किया गया है।
 - दिशानिर्देश रेत खनन प्रक्रिया की नगिरानी के लिये ड्रोन और नाइट वज़िन जैसी नई नगिरानी प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर भी विचार करते हैं।

सोन नदी

- सोन नदी, **मध्य भारत की एक चरिस्थायी नदी है** और गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है।
- **छत्तीसगढ़ में अमरकंटक पहाड़ी** के पास से निकलकर, यह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर बहती है, तथा अमरकंटक पठार पर जलप्रपात बनाती है।
 - यह बिहार के पटना के नजिक गंगा में मलि जाती है।
- सहायक नदियों में घाघर, जोहला, छोटी महानदी, बनास, गोपद, रहिंद, कन्हर और उत्तरी कोएल नदी शामिल हैं।
- प्रमुख बाँधों में **मध्य प्रदेश में बाणसागर बाँध और उत्तर प्रदेश में पपिरी के पास रहिंद बाँध** शामिल हैं।



UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

??????

Q. तटीय बालू खनन, चाहे वह वैध हो या अवैध हो, हमारे पर्यावरण के सामने सबसे बड़े खतरों में से एक है। भारतीय तटों पर बालू खनन के प्रभाव का, वशिष्ट उदाहरणों का हवाला देते हुए, विश्लेषण कीजिये। (2019)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/illegal-sand-mining-2>